प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नैटवर्क का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री भजनलाल कार्यक्रम में जयपुर से जुड़े, लाभार्थियों से संवाद किया

झारसुगुड़ा/जयपुर, 27 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी नेटवर्क सेवाओं के माध्यम से देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की कंपनियों ने देश को दुनिया के उन पांच देशों की सूची में ला खड़ा किया है, जिनके पास 4 जी सेवाएं शुरु करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुडा से बीएसएनएल की 4जी नेटवर्क सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब टेलीकॉम की दुनिया में 2जी, 3जी, 4जी जैसी सेवाएं शुरू हुईं तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। इन तकनीकों के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर था, ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए हमने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की यह जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। मोदी ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4जी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत और कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं का सबसे अधिक फायदा आदिवासी क्षेत्रों के साथ ही, दूर-दराज के गांवों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल पाएंगी। इससे बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, सुदूर क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल का मूल्य जानने में तथा मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिए चिकित्सकों से सलाह लेने में सुविधा होगी। इसके साथ ही, सीमावर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हमारे जवानों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा, वे सुरक्षित कनेक्टिविटी के साथ आपस में बात कर पाएंगे। मोदी ने कहा कि बीएसएनएल के आज शुरू हुए टॉवर आसानी से 5जी सेवाओं के लिए भी अपलोड हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअली जुड़े। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत में बीएसएनएल के 92 हजार 633 4जी टावरों का उद्घाटन किया गया है। इनमें से 5 हजार 655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडीसा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4 जी नैटवर्क शुरु किया। मुख्यमंत्री भजनलाल इस कार्यक्रम में बीएसएनएल के अधिकारियों, राजनेताओं व राज्य के अधिकारियों के साथ वर्चुअली जुड़े।

- **मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व के उन पाँच देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास 4जी सेवा की पूरी स्वदेशी टैक्नॉलजी है।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डिजिटल भारत निधि परियोजना के माध्यम से बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता 27 हजार 106 गांवों में 4जी कनेक्टिविटी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 हजार 903 टावर पहले ही तैयार हो चुके हैं, जो 26 हजार से ज्यादा गांवों को कवर करते हुए लगभग 20 लाख घरों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

बीएसएनएल राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल भारत पहल से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने बीएसएनएल की प्रगति में मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने बीएसएनएल 4जी सेवा के लाभार्थियों से आत्मीय संवाद भी किया। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा सहित, बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

'निर्दोष लोगों पर फायरिंग से जनता का भरोसा टूटा है'

लद्दाख के शीर्ष भाजपा नेता और पूर्व सांसद जे. नामग्याल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दुख जताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। लद्दाख के एक शीर्ष भाजपा नेता ने सरकार के स्थिति संभालने के तरीके और बुधवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों के मारे जाने पर सवाल उठाए हैं। न्यायिक जांच की मांग करते हुए, जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, जो इस क्षेत्र में भाजपा के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद हैं, ने कहा है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और "हमारे युवाओं के बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए।"

लद्दाख के उप राज्यपाल को लिखे पत्र में नामग्याल ने कहा कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी से जनता का भरोसा डगमगा गया है। उन्होंने एक समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्र में नामग्याल ने कहा है, "यह गंभीर चिंता का विषय है। इस संकट को अधिक धैर्यपूर्वक संभाला जा सकता था। जहाँ हिंसा और आगजनी की निंदा की जानी चाहिए, वहीं निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी ने जनता का भरोसा हिला दिया है।"

लद्दाख को राज्य का दर्जा एवं संवैधानिक सुरक्षा दिये जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी बुधवार को हिंसक हो गए। एक झुंड ने भाजपा कार्यालय, लद्दाख हिल काउंसिल कार्यालय जलाया और पुलिस तथा सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की गाड़ियों को आग लगा दी। भीड़ ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस के अनुसार, पत्थरबाजी में करीब 30 पुलिस और सीआरपीएफ जवान घायल हुए।

जवाब में सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और अन्य बहुत से घायल हो गए।

नामग्याल ने उपराज्यपाल कवीन्दर गुप्ता को भेजे गये अपने पत्र में कहा है, "मैं भारी मन से, लद्दाख के लोगों की ओर से और व्यक्तिगत रूप से तथा 17वीं लोकसभा के पूर्व सदस्य के नाते, 24 सितम्बर 2025 को लेह में हुई दुखद घटना पर गहरा दुःख और अफसोस व्यक्त करता हूँ। जो शुरू में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति थी, वह हिंसा में बदल गई, जिससे चार युवाओं की जान गई, कई घायल हुए, संपत्ति को नुकसान पहुँचा और हमारा समुदाय भयग्रस्त हो गया।"

पत्र में नामग्याल ने लिखा, "लद्दाख एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है और हमारे युवाओं के बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए।"

नामग्याल उस समय लद्दाख के भाजपा सांसद थे, जब अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के बंटवारे के बाद, लद्दाख को अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इसे इसके विशेष दर्जे से वंचित कर दिया गया था।

नामग्याल ने कहा, पूरे "लद्दाख में व्यापक पीड़ा है और नागरिक निर्दोष मृतकों के लिए न्याय, घायल लोगों के लिए राहत और ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसकी गारंटी चाहते हैं।"

लद्दाख में न्यायिक जांच की मांग तेज हो रही है गोलीबारी में मारे गए चार लोगों के शव गुरुवार को परिवारों को सौंपे जाने के बाद, इस घटना की न्यायिक जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मृतकों में से एक पूर्व सैनिक भी था, जो लद्दाख स्काउट्स का सदस्य था।

यह संकट तब शुरू हुआ, जब प्रदर्शनकारी उस स्थल से बाहर निकले, जहाँ ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे। वांगचुक को शुक्रवार को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (नैशनल सिक्योरिटी एक्ट-एनएसए)) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

जहाँ सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, वहीं लद्दाखी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की अनियंत्रित गोलीबारी का आरोप लगाते हुए, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जो नागरिकों पर गोली चलाने में शामिल थे।

लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने कहा, "यह सुरक्षा बल के अंधाधुंध प्रयोग का स्पष्ट मामला है। मैं प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और कई लोगों को आईं चोटों की निष्पक्ष और न्यायिक जांच की मांग करता हूँ।"

यह मांग करने वालों में लेह एपेक्स बॉडी और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी शामिल हैं। लद्दाख के इन दोनों प्रभावशाली संगठनों ने वांगचुक के हिंसा में शामिल होने के दावों और लेह में हुए प्रदर्शनों में किसी बाहरी हाथ के होने के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग, जो जम्मू-कश्मीर के डोडा के रहने वाले थे और बुधवार को घायल हुए, "वे तो उस समय वहां खड़े हुए थे, और अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान वे घायल हुए।"

- **नामग्याल ने कहा, इस संकट से धैर्य से निपटा जाना चाहिए था। दमनकारी एक्शन से जहाँ तक हो बचना चाहिए।**
- **नामग्याल ने हिंसा की न्यायिक जाँच की माँग की और कहा, लद्दाख बहुत नाज़ुक मोड़ पर है। हमारे लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।**

तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 की मौत

एक्टर विजय की करुर में आयोजित रैली में मची भगदड़ में मृतकों में 16 महिलाएं, 9 पुरुष व 6 बच्चे शामिल हैं

तमिलनाडु, 27 सितंबर। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम को भगदड़ मच गई। इसमें 31 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 महिलाएं, 9 पुरुष और 6 बच्चे शामिल हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम ए सुब्रमणियन ने यह जानकारी दी। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

जानकारी के मुताबिक, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विजय के भाषण के दौरान भीड़ बढ़ ने से भगदड़ जैसे हालात बन गए।

भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हालात बिगड़ते देख विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की। इसके बाद वे भाषण छोड़कर निकल गए। सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि विजय की रैली में भगदड़ जैसी स्थिति और कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली। करूर प्रशासन से मिली जानकारी चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम और जिला कलेक्टर को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। मंत्री अंबिल महेश को भी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को करूर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम स्टालिन ने करूर में आम जनता से डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की। करूर में रैली के दौरान अभिनेता और राजनेता विजय ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मंत्री ने गलत कारण से जिले को देश भर प्रसिद्ध बना दिया है। डीएमके ने करूर में हवाई अड्डा बनाने का वादा किया था, लेकिन अब उसने केंद्र से हवाई अड्डा बनाने का आग्रह किया है।

इससे पहले नमक्कल में अभिनेता विजय ने रैली की। यहां भी रैली में भारी भीड़ उमड़ी। विजय ने भाजपा के खिलाफ अपना पुराना रुख दोहराया और एआईएडीएमके के साथ उनके गठबंधन को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है और जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2026 में तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके को वोट देना भाजपा को वोट देना होगा।

- **विजय की रैली में भारी भीड़ उमड़ी कई लोग बेहोश होने लगे, इस पर विजय ने अपना भाषण रोक दिया लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और वहां से चले गए।**
- **मुख्यमंत्री स्टालिन ने घटना पर दुख जताया और प्रशासन को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।**

4-5 अक्टूबर को चुनाव आयोग का बिहार दौरा

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए चार और पांच अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगी।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस एवं व्यय) की एक संक्षिप्त बैठक भी 3 अक्टूबर को नयी दिल्ली के द्वारका में आयोग के "भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम)" में आयोजित की जाएगी।

डेरा सच्चा सौदा को 8 साल बाद बैंक खाते वापस मिल

सिरसा, 27 सितंबर। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट को शिक्षण संस्थानों, अस्पताल और रोजाना खर्च के लिए बैंक खातों के संचालन की छूट दे दी है।

गौरतलब है कि इससे पहले न्यायालय के एक आदेश पर डेरा सच्चा-सौदा से जुड़े शिक्षण संस्थानों व अस्पताल को चलाने के लिए सिरसा के उपायुक्त, सिविल अस्पताल के डिप्टी सीएमओ, जिला शिक्षा अधिकारी और दो सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपलों पर आधारित एक गवर्निंग बॉडी का गठन किया हुआ था जो इनका संचालन कर रही थी।

उल्लेखनीय है कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को 25 अगस्त 2017 को पंचकूला सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सिरसा ,पंचकूला व कुछ अन्य स्थलों पर हिंसा फैल गई थी। फैली इस हिंसा में 32 लोगों की मौत हो गई थी और 118 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था।

उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सभी बैंक खाते सील कर दिए गए थे।

तीन दिन बाद लेह में कर्फ्यू में ढील, पर मोबाइल इंटरनैट बंद

लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से मोबाइल इंटरनैट बंद है

श्रीनगर, 27 सितंबर। लद्दाख के लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा घायल होने के तीन दिन बाद शनिवार, को कर्फ्यू में ढील दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि ढील के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही।

इससे पहले दिन में लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एस.डी. सिंह जामवाल ने कहा कि लेह में कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा, "हम कर्फ्यू को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति लाना है और हम लोगों की समस्याओं को समझते हैं।"

अधिकारियों ने बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने और राजस्थान की जोधपुर जेल में स्थानांतरित किए जाने के एक दिन बाद सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। लेह पुलिस ने यात्रियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कई जगहों पर नाके लगाए हैं।

एक अधिकारी ने कहा, "बुधवार की हिंसा के बाद, कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।" वांगचुक की गिरफ़्तारी के बाद से निलंबित मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ अभी भी बंद हैं।

लद्दाख में बुधवार से ही तनाव व्याप्त है, जब केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की माँग को लेकर वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। दो दिन बाद, वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसस) के तहत हिरासत में ले लिया गया।

लद्दाख प्रशासन ने हिरासत को उचित ठहराते हुए कहा कि लेह में "शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने" और आगे कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक था। अधिकारियों ने कहा कि वांगचुक के "भड़काऊ" भाषणों, नेपाल आंदोलन, अरब स्प्रिंग के संदर्भों और "भ्रामक वीडियो" की श्रृंखला ने 24 सितंबर को हिंसक अशांति को जन्म दिया। सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के एक समूह, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने हालांकि कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में वांगचुक की कोई भूमिका नहीं थी।

- **लद्दाख पुलिस प्रशासन ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान हालात शांतिपूर्ण रहे।**
- **लेह के सामाजिक -धार्मिक व राजनैतिक संगठनों के समूह लेह एपैक्स बॉडी ने कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शन में वांगचुक की कोई भूमिका नहीं थी।**

राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना

नयी दिल्ली, 27 सितंबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के चार देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गांधी इस यात्रा के दौरान, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील कोलंबिया सहित चार देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे। कांग्रेस के एक अन्य सूत्र ने कहा "गांधी की यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा है। भारत और दक्षिण अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से अपने रिश्ते साझा किए हैं। गांधी की यह यात्रा इस परंपरा को जारी रखते हुए व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान में सहयोग के नए रास्ते खोलेगी।"

बरेली में दो दिन के लिए इंटरनैट बंद

लखनऊ, 27 सितंबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ के बाद हुई पत्थरबाज़ी के अब सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फ़ैसला किया है। इस बीच, जुमे की नमाज के बाद बवाल का मामला में घटना की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

प्रदेश के गृह सचिव गौरव दयाल के निर्देश पर बरेली में दूरसंचार (इंटरनेट) सेवाएं निलंबित रहेंगी। इसकी अवधि 48 घंटे रहेगी।

- **सांप्रदायिक तनाव के बाद सरकार ने कई सख्त कदम उठाए। विवाद की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित।**

एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संवेदनशील बनाती है। यहाँ कोई भी आंतरिक अस्थिरता भारत, चीन सीमा, "लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर निगरानी रखने की क्षमता को कमजोर करती है, जहाँ के जमीनी हालात, 2020 में चीन की सेना की गलवान झड़पों के बाद से बदल चुके हैं। इसलिए यह अशांति केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है।

इस हफ्ते के विरोध प्रदर्शन, अधूरे राजनीतिक वादों, पर्यावरणीय क्षति और दिल्ली की कथित उपेक्षा के कारण भड़के हैं, जिसने लद्दाख की शांतिपूर्ण छवि को तहस-नहस कर दिया है। चेलानी के अनुसार, यह असंतोष खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा, "लद्दाख की अस्थिरता भारत की व्यापक सुरक्षा रणनीति को कमजोर कर सकती है, खासकर चीन और पाकिस्तान से जुड़ी जटिल चुनौतियों का सामना करने में।"

स्थिति तब और उलझ गई, जब सरकार ने आरोप लगाया कि मौजूदा आंदोलन का चेहरा, सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंध हो सकते हैं। लद्दाख पुलिस और सीबीआई ने वांगचुक की गतिविधियों की जांच शुरू की है, जिसमें विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन और फरवरी में उनके पाकिस्तान दौरे को खंगाला जा रहा है।

अधिकारियों का दावा है कि हाल ही में गिरफ्तार एक पाकिस्तानी नागरिक ने वांगचुक के विरोध प्रदर्शन के वीडियो सीमा पार भेजे थे, जिससे सीमा पार से रुचि या समन्वय की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वांगचुक ने "अरब स्प्रिंग" और "जनरेशन ज़ैड क्रांतियों" का जिक्र करते हुए, उकसाने वाले भाषण दिए, जो हालिया हिंसा के भड़कने का कारण हो सकते हैं।

तथापि, वांगचुक ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और स्थानीय परेशानियों पर आधारित है, किसी विदेशी एजेंडा पर नहीं। वे जोर देकर कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा जैसे अधूरे वादों से उपजी नाराजगी का नतीजा हैं। उनके कथित पाकिस्तान संबंधों का कोई ठोस सबूत अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है और न ही कोई औपचारिक आरोप तय किए गए हैं।

फिर भी, लद्दाख जैसा रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाका होने के कारण, विदेशी दखल की आशंका मात्र भी हालात को गंभीर बना देती है। सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसे दावे मजबूत होते हैं तो उन्हें स्थानीय विरोध को बाहरी प्रभाव का हिस्सा बताया जा सकता है, जिससे सुरक्षा कड़ी करने और असंतोष पर नियंत्रण बढ़ाने को जायज ठहराया जा सकता है।

इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अशांत लद्दाख भारत, चीन सीमा "लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर सुरक्षा का ध्यान भटका सकता है, जहां चीन लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह स्थानीय सहयोग को कमजोर कर सकता है, जो खुफिया जानकारी जुटाने और सैनिकों को समर्थन देने के लिए जरूरी है। यह दुश्मनों को प्रोपेगेंडा, गलत सूचना या गुप्त दखल के अवसर भी दे सकता है और भारत की सीमा नीति को जटिल बना सकता है, जहां चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत का खतरा हमेशा बना रहता है।

चेलानी का कहना है, बीजिंग का रिकॉर्ड बताता है कि वह भारत के सीमावर्ती इलाकों में आंतरिक खामियों, जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में देरी या राजनीतिक अलगाव, का फायदा उठाकर सामरिक और मानसिक बढ़त हासिल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में, सीमा पार प्रभाव के आरोप, चाहे अप्रमाणित ही क्यों न हों, आपसी भरोसे को कमजोर कर सकते हैं और राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचा सकते हैं।

चेलानी ने सोच समझकर गैर दमनकारी कदम उठाने की सलाह दी है। उनका कहना है, नई दिल्ली को स्थानीय समुदायों से लगातार संवाद करना चाहिए, भरोसा बनाने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए और ऐसे उपायों से बचना चाहिए, जो लोगों को और दूर कर दें। वे चेतावनी देते हैं कि कठोर कदम केवल नाराज़गी को और बढ़ाएंगे तथा हाशिये पर धकेले जाने की धारणा को मजबूत करेंगे, जिसका फायदा विरोधी ताकतें आसानी से उठा सकती हैं। तनाव कम करने के लिए विशेषज्ञ आर्थिक अवसर, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सुरक्षा में समानांतर निवेश की सलाह देते हैं। खासकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन और शासन व स्वायत्तता की मांगों पर ठोस प्रगति लंबे समय तक स्थिरता का आधार बन सकती है। चेलानी का कहना है, ये प्रयास न केवल स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, बल्कि बाहरी ताकतों द्वारा असंतोष का फायदा उठाए जाने का खतरा भी कम करेंगे।

संदेश साफ है, लद्दाख में शांति बहाल करना सिर्फ आंतरिक व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है। चीनी सैनिकों के विवादित चोटियों पर डटे रहने और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की सक्रियता के बीच लद्दाख भारत की हिमालयी रक्षा का केन्द्र है। यहां की कोई भी आंतरिक हलचल पूरे उत्तरी मोर्चे पर असर डाल सकती है।

चेलानी की चेतावनी एक तत्कालिक हकीकत दिखाती है, भारत अपनी सबसे संवेदनशील रणनीतिक सीमा पर अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजनीतिक संवाद, आर्थिक भागीदारी और संवेदनशील शासन का संतुलित मेल ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि लद्दाख भारत की संप्रभुता का किला बना रहे, कमज़ोरी नहीं।

- **वांगचुक दूसरी ओर पुरजोर ढंग से कह रहे हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है तथा कोई विदेशी हाथ नहीं है। आंदोलन का आधार, केन्द्रीय सरकार के खिलाफ जनता में वादाखिलाफी की शिकायत घर कर गई है, जहाँ तक क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की बात है तथा स्थानीय जनता केन्द्रीय सरकार पर भावात्मक दूरी व अवहेलना बरतने का आरोप लगा रही है।**
- **लद्दाख, चीन के कब्जे में मौजूद अक्साई चिन तथा पाक अधिकृत भूमि के बीच में है तथा चीन भारत के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाकर जनता में असंतोष को हवा देता है। स्थानीय असंतोष अगर बढ़ जाता है तो जमीनी जानकारियाँ भारत के सुरक्षा बलों तक नहीं पहुँच पातीं तथा स्थानीय स्तर पर इंटैलिजैंस इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है।**

सदा की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनेगी और पटना को बेतिया से जोड़ेगी।

बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट ने राज्य में 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल लाइन को डबल करने की भी मंजूरी दी। यह रूट कोयला, क्लिंकर, फ्लाई ऐश और सीमेंट जैसी वस्तुओं की माल ढुलाई के लिए अहम माना जाता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2192 करोड़ रुपये है।

इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें आठ नई ट्रेनों की शुरुआत भी शामिल है। इनमें नई बनाई गई "अमृत भारत" श्रेणी की ट्रेनें भी हैं। इनमें से पाँच लंबी दूरी की ट्रेनें बिहार के विभिन्न हिस्सों को नई दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से जोड़ेंगी, जबकि बाकी तीन ट्रेनें स्थानीय मार्गों पर चलेंगी।

विपक्ष ने बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जबकि राज्य में एनडीए की डबल इंजन सरकार है। सबसे तीखी आलोचना जन सुराज नेता और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां गुजरात और दूसरे राज्यों में उद्योग लगा रहे हैं, वहीं बिहार के लिए नॉन-एसी अमृत भारत ट्रेनें शुरू कर सस्ते मजदूरों को दूसरे विकसित राज्यों में काम करने के लिये भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी आलोचनाओं का एनडीए सरकार की परियोजना, घोषणाओं पर कोई असर नहीं दिख रहा। इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट ने भागलपुर लाइन के मोकामा-मुंगेर सेक्शन के निर्माण और भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन को डबल करने को मंजूरी दी, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत हो जायेगी।

ट्रंप को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देते हुए, उनका नाम सूची से हटा दिया है। नॉर्वे, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के दिन, 10 दिसंबर को शांति पुरुस्कार प्रदान करता है। नोबेल शांति पुरुस्कार उन नोबेल पुरुस्कारों में से एक है, जो स्वीडिश उद्योगपति, आविष्कारक और हथियार निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से शुरु किया गया था। इसके अलावा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा या चिकित्सा विज्ञान और साहित्य में भी नोबेल पुरुस्कार दिए जाते है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908